

जमीन पट्टे के नाम हुई धोखाधड़ी का मामला कलेक्टर के पास पहुंचा

जनसुनवाई में लगाई कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार, एसडीएम के निर्देश के बाद नहीं हुई कोई जांच



जिला जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे हीना बैरागी और राहुल अग्रवाल।

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खण्ड की बड़ी पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत सारंगी में सरपंच-सचिव द्वारा सरकारी भूमि पर पट्टे देकर धोखाधड़ी करने का मामला जिला कलेक्टर नेहा मोणा के पास पहुंच गया है। शिकायतकर्ता राहुल

अग्रवाल और हिना बैरागी ने जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंच कर उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

नहीं हुई कोई जांच, एसडीएम के निर्देश उड़े हवा में

शिकायतकर्ताओं ने इससे पहले जनसुनवाई कार्यक्रम पेटलावद में आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। शिकायत के बाद एसडीएम तनुश्री मोणा ने जांच के लिए पत्र जनपद पंचायत को तुरंत भेज दिया था। जिसके बाद जाँच दल बनाया गया था। लेकिन कोई जांच होने की जानकारी सामने नहीं आई। एक शिकायत की जांच शुरू

भी नहीं हो पाई थी कि, इस प्रकार की धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आ गया था। शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी हेतु आवेदन जनपद सीईओ को दिया गया तो पता लगा कि, इस विषय में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। शिकायतकर्ता राहुल अग्रवाल ने बताया कि, जनपद सीईओ को आवेदन देकर मामले

में हुई जांच के प्रमाणित दस्तावेज मांगे लेकिन जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि, तहसीलदार साहब नहीं है इसलिए जांच में देरी हो रही है। जनपद के अधिकारियों के रवैये को देखते हुए मामले की शिकायत कलेक्टर से की है।

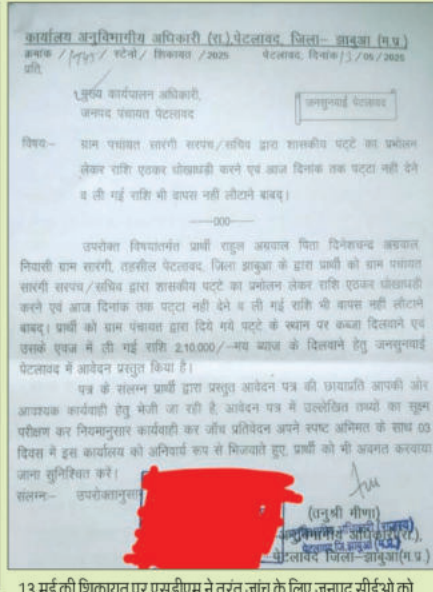
थाने पर भी दिया आवेदन

शुक्रवार को हीना बैरागी ने भी पुलिस थाना पेटलावद में आवेदन देकर धोखाधड़ी करने की

शिकायत की है। इससे पूर्व राहुल अग्रवाल भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। इस प्रकार के मामलों में प्रशासन और पुलिस पर भारी राजनीतिक दबाव रहता है और लंबे समय से ग्राम पंचायत की सरपंच फुंदी बाई मेडा आने वाले समय में पेटलावद विधानसभा में भाजपा का चेहरा बन सकता है, ऐसे में इस गंभीर मामले सहित ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपो से निकलने की कड़ी चुनौती उनके सामने होगी।



जनसुनवाई में दर्ज शिकायत की पावती।



13 मई की शिकायत पर एसडीएम ने तुरंत जांच के लिए जनपद सीईओ को लिखा पत्र।

श्रीमद भागवत कथा के अंतिम दिन भक्त झूमे

माही की गूंज, भामला।

मादलदा रोड पर 21 तारीख से चल रही सप्तदिवसीय श्रीमद भागवत कथा का समापन मंगलवार रात्रि को आयोजन के साथ किया गया। रात 8 बजे से लेकर देर रात 2 बजे तक चले इस कार्यक्रम में ग्राम सहित समीपवर्ती क्षेत्रों और राजस्थान सीमा से सटे बड़ी सरवा, पाटन आदि गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे।

कथा वाचन पूज्य गायत्री जी वैष्णव ताजुखेड़ा (ताल) के मुखारबिंद से हुआ। सात दिन तक उन्होंने श्रीमद भागवत कथा की अमृतवाणी से भक्तों को भावविभोर किया। अंतिम दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कथा वाचक को बगी पर विराजमान कर पूरे ग्राम में शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में बड़-चढ़कर भाग लिया। शाम को प्रसादी स्वरूप भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।



श्री राठोड़ को सनातन धर्म रक्षक सेना का संरक्षक मनोनीत किया

माही की गूंज, काकनवानी।

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डाइमचंद राठोड़ को सनातन धर्म रक्षक सेना के संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य संत आचार्य श्री विजय जी महाराज की सर्व सम्मति से की गई है।

डाइमचंद राठोड़ लंबे समय से समाज सेवा, धर्म रक्षा एवं गो सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वही वे कलाल समाज ज्ञानुआ-अलीराजपुर के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। उनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्रभक्ति को देखते हुए संगठन ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।

संस्था ने उन्हें मनोनयन पत्र भेंट करते हुए आशा जताई कि, वे अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे और देश एवं धर्म के प्रति अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर संस्था के अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

श्री राठोड़ ने इस अवसर पर कहा कि, वे संस्था के उद्देश्यों पर दृढ़ रहते हुए धर्म और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने इस विश्वास के लिए संगठन के पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया।



पूरे जिले में वैध-अवैध मेडिकलों की जांच होना जरूरी, लायसेंस और डिग्री पर नाम किसी का, संचालन किसी ओर का मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मियों के पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं, फिर भी संचालक ओने-पोने दामों पर रख लेते हैं काम पर

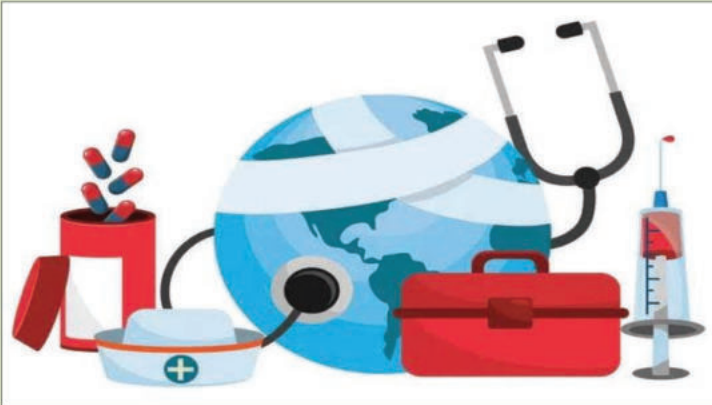
माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो जिले में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी फार्मासिस और दवा दुकानों की अनियमितता में एक अलग ही किर्तिमान दिखाई पड़ रहा है। कहीं-कहीं तो इतनी हद है कि, दवा दुकानों के लायसेंस किसी के नाम होता है और कोई ओर ही उसका संचालन कर रहा होता है। जिले में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें एक ही व्यक्ति की फार्मा डिग्री पर कई मेडिकलों का संचालन हो रहा है। कई मामलों में पहले तो संचालक के पास खुद दवाई दुकान चलाने हेतु कोई लायसेंस या डिग्री नहीं होती उस पर सितम यह कि, उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी 'नीम हकीम खतरा ए जान' वाली दिखाई देती है। कई मेडिकलों पर कर्मचारी 10 वीं या 12 वीं पास या फेल होकर मेडिकल पर जांब करते नजर आते हैं। हालांकि यह लोग संचालक की निगरानी में काम करते हैं। बावजूद भी प्रकाश में आते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल स्टोर से इसी तरह दवाई लेने और देने के बाद उस दवाई से एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन व पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल को सील कर दिया था। मेडिकल संचालक व कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब मेडिकल संचालक जमानत पर बाहर है। इस पूरे मामले में जो खास बात सामने निकल कर आई वह यह थी कि, मेडिकल संचालक की उपस्थिति के बावजूद मेडिकल पर काम कर रही युवती ने गलती से गलत दवाई दे दी थी। जिसे खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई।

यह मामला उजागर होने के बाद जिले में संचालित हो रहे तमाम मेडिकल संह के घरे में आ खड़े हुए हैं। सवाल यह कि, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब जिले में संचालित हो रहे तमाम मेडिकलों की जांच कब करेगा? या इन मेडिकल संचालकों की डिग्री या मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता की जांच कब होगी? हालांकि कई

बार ऐसी खबरें देखने में आती हैं जब जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला, दवाई दुकानों का निरीक्षण करता दिखाई देता है। लेकिन इस निरीक्षण में कितनी अनियमितताएं मिली हैं इसकी जानकारी कोई कभी नहीं देता। सुत्र तो यह भी बताते हैं कि, निरीक्षण के लिए पहुंची टीम की खबर वैसे ही दुकानदारों को हो जाती है जैसे झोलाछाप डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की दबिश की खबर लग जाती है। नतीजे जो निकल कर सामने आते हैं वह भी चौकाने वाले ही होते हैं। जब टीम पहुंचने की खबर लगती तो मेडिकल संचालक अपनी दुकानों पर ताले जड़ फरार हो जाते या फिर जिस तरह की सेटिंग झोलाछाप करते हैं शायद वैसे ही सेटिंग अवैध मेडिकल संचालक भी कर लेते हैं और निरीक्षण करने पहुंची टीम चंद टुकड़ों के आगे नतमस्तक होकर लौट आती है।

मगर कल्पना भर कीजिए कि, जिले भर में कितने मेडिकल संचालित हो रहे हैं, इनमें कितने लायसेंस या फार्मा डिग्री वाले हैं और कितने अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। इनका कोई रिकार्ड भी प्रशासन के पास है या फिर यहाँ भी अंधेर गद्दी ही है। सवाल यह भी है कि, इन वैध-अवैध मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मचारियों की क्या योग्यता है...? क्योंकि बहुत कम मानदेय में फार्मा डिग्री वाले कर्मचारी जिले में मिलना नामुमकिन है। जिले में किसी मेडिकल पर कार्य करने के लिए जो योग्यता लागू है वह सिर्फ इतनी है कि वह कम से कम 10 वीं या 12 वीं कक्षा पढ़ा हुआ हो और उसे इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए। और इस तरह के बेरोजगारों की जिले में कोई कमी नहीं है। मेडिकल संचालक ऐसे लोगों को बहुत अल्प मानदेय देकर अपनी दुकान पर रख लेते हैं। सुत्र बताते हैं कि, इसके पीछे मेडिकल संचालक का यह तर्क होता कि, समय के साथ-साथ अनुभव हो जाता है। बात भी सही है, लेकिन जब अनुभव लेते-लेते एक मेडिकल का साधारण सा कर्मचारी डॉक्टर बनने लगे तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है ' 'नीम हकीम खतरा ए जान' '। मतलब सीधा सा है आधा डॉक्टर आपकी जान के लिए खतरा है और इस तरह के आधे-अधूरे डॉक्टर जिले में संचालित हो रहे लगभग हर मेडिकल या दवाई की दुकान पर आसानी से मिल



जाते हैं।

विडम्बना यह कि, पिछले दिनों जिला मुख्यालय के एक मेडिकल पर हुई इसी तरह की घटना के बाद अब तक ना तो स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदान में नजर आया और ना ही प्रशासन ने इस ओर कोई रूची भर दिखाने की कोशिश की। जिस मेडिकल पर यह घटना क्रम हुआ सिर्फ उसी एक मेडिकल व उसके संचालक पर कार्रवाई की गई। उसके अलावा जिले के किसी भी मेडिकल पर जांच या कार्रवाई का कोई समाचार अब देखने को नहीं मिला है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले में मेडिकल दुकानों पर बैठे आधे-अधूरे डॉक्टरों से जिले की जनता को कितना खतरा है।

रही बात मेडिकलों पर अमानक दवाईयों के विक्रय की तो यह कौन नहीं जानता कि, मेडिकलों पर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। जब जिला मुख्यालय के मेडिकलों पर अमानक और अवैध दवाईयों का विक्रय हो रहा है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे मेडिकलों पर क्या-क्या नहीं मिलता होगा। वैसे भी जिले में कई मेडिकल ऐसे हैं जहाँ से नर्सियों को नशे की खुशक उपलब्ध हो जाती है तो लगभग हर मेडिकल से नर्सड़ी या कोई आम आदमी भी सुई और सिरिज आसानी से ले सकता है। नशीली दवाईयों की अगर बात करें तो नर्सड़ी इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, कई दवाईयां ऐसी हैं जो मेडिकलों पर वैध रूप से ही मिल जाती हैं। इसके लिए किसी तरह की कोई डॉक्टर की चिड़्य या परामर्श की

आवश्यकता नहीं होती है। जबकि मेडिकल संचालक भी कई बार यह समझता है कि, जो दवाई दी जा रही है उसमें नशा है। इस तरह की दवाईयों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें खुजली, जुखाम, सर्दी, खासी की दवाएं भी शामिल हैं। कई दवाईयों में एलकोहल की मात्रा अधिक होती है। मगर मेडिकल संचालक कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता है कि, दवाई लेने आया व्यक्ति किस लिए दवाई ले रहा है। अगर दवाई लेने आया ग्राहक पहचान या मेडिकल का खाता धारक है तब तो सवाल ही नहीं उठता की उससे किसी तरह की पुछताछ की जाए।

अवैध या प्रतिबंधित दवाईयों की अगर बात करें तो लगभग जिले के हर मेडिकल पर यह संचालक के पहचान वालों और खाताधारकों के लिए उपलब्ध रहती है। गर्भपात से संबंधित दवाईयां इनमें प्रमुख हैं। मगर मजाल है कि, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन इनकी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। मेडिकल संचालक के अलावा मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी भी अपने जान पहचान व रिश्तेदारों की डिमांड बहुत ही आसानी से पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वह दवाई प्रतिबंधित ही क्यों न हो। गर्भपात व सेक्स संबंधी दवाएं भी मेडिकलों से इसी तरह सप्लाय होती हैं। मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी अपने जान पहचान व रिश्तेदारों को इन दवाओं की बकायदा होम डिलेवरी भी करते हैं। यह और बात है कि, यह मेडिकल संचालक के संज्ञान में होती है या नहीं।

कोरोना काल की तरह अब वयों नहीं

कोरोना काल में मेडिकलों पर लगे प्रतिबंध हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। कोरोना काल मतलब सबसे खराब समय, मगर इस दौरान सरकार ने मेडिकलों पर ऐसी नकेल कसी थी कि मेडिकल से बिकने वाली हर दवाई का डाटा स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन चेक कर रहा था। सदिग्ध होने पर मेडिकल संचालक खुद ग्राहक को यह समझाईश देते थे कि, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं दी जाएगी। बकायदा ग्राहक की एंट्री, ली गई दवाई की एंट्री सबकुछ ऑन रिकार्ड हो रहा था। स्थिति यह थी कि, मेडिकल से किसी तरह की कोई भी अवैध दवाई नहीं बिक पा रही थी। गलती होने पर मेडिकल

संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की धौंस इतनी तगड़ी थी कि संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवाई नहीं दे रहे थे। मगर अब स्थिति फिर से ढाक के तीन पात है।

वैसे अगर देखा जाए तो जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की जिस तरह भरमार है वैसे ही अवैध मेडिकलों और उन पर काम करने वाले अयोग्य कर्मचारियों की भी भरमार है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि, ' 'नीम हकीम खतरा ए जान' ' इसी तरह झोलाछाप और अवैध मेडिकल संचालक या मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी भी झोलाछाप की तरह ही आधे-अधूरे डॉक्टर ही बनकर काम कर रहे हैं। जो जिले की जनता के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

वैसे तो मेडिकल संचालन के लिए फार्मा डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन जिले में कई मेडिकल इस गाइड लाइन को पूरा करते नहीं दिखाई देते हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि, अगर कोई मेडिकल का संचालन खेरची दुकान के तौर पर करता है तो उसे फार्मा डिग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई थोक दवाईयों का व्यापार करता है तो उसे इस तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस शर्त यह रहती कि, वे किसी की भी डॉक्टर की पर्ची से दवाई नहीं दे सकते सिर्फ और सिर्फ मेडिकल संचालकों को ही थोक सप्लाय कर सकते हैं। नतीजा यह है कि, जिले में कई मेडिकल इसी तरह की फार्मा थोक एजेंसियों की आड़ में संचालित हो रहे थे और होंगे। कई झोलाछाप भी इसी तरह की फार्मा एजेंसियों के नाम से मेडिकल का संचालन कर रहे हैं, तो कई मेडिकल भी ऐसे हैं जो एजेंसी के नाम पर दवाईयों का थोक व्यापार ना करते हुए खेरची दवाईयां बैच रहे हैं। इस तरह के अवैध मेडिकलों पर सभी तरह की वैध-अवैध और प्रतिबंधित दवाई भी आसानी से मिल जाती है।

अब देखा जा रहा है कि, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जिले में संचालित हो रहे इस तरह के मेडिकलों की जांच पड़ताल कब करेगा या फिर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए हर एक अवैध मेडिकल के बदले किसी न किसी जिलेवासी को अपनी जान गवानी पड़ेगी। अगर जिलेवासीयों की जान से होने वाले खिलवाड़ को रोकना है तो फिर जांच जरूरी है। चाहे वह वैध-अवैध मेडिकल के संचालकों की हो या मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता की हो या फिर अवैध और प्रतिबंधित दवाईयों की जांच तो जरूरी है।

भ्रष्टाचार में लिफ्ट सचिव को हटाने की मांग को लेकर सरपंच और ग्रामीण धरने पर बैठे

12 लाख का भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी सचिव को नहीं हटाना मिली भगत की निशानी - गामड़

माही की गूंज, पेटलावद।

सोमवार को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीण ग्राम पंचायत के सरपंच बालूसिंह गामड के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मण मुनिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सचिव को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जनपद कार्यालय का मुख्य द्वार रोक कर बैठे ग्रामीणों को जनपद के अधिकारी राजेश दीक्षित एवं तहसीलदार निगवाल ने समझाझर देने की कोशिश की लेकिन सरपंच सहित ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे और सचिव के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे।

सरपंच बालूसिंह गामड ने बताया कि, ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मण सिंह मुणिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत मेरे द्वारा की गई थी जिसकी जांच जनपद द्वारा बनाई गई टीम द्वारा की गई थी और सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करना साबित हुआ। इसके बावजूद सचिव को ग्राम पंचायत से नहीं हटाया गया।

सचिव का बड़ा भ्रष्टाचार

जनपद द्वारा बनाई गई टीम द्वारा की गई जांच में सचिव लक्ष्मण सिंह मुणिया के कार्यकाल में हुए निर्माण, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की राशि में 12 लाख 9 हजार रुपये की हेराफेरी होना पाया गया एवं उसकी वसूली के आदेश भी जारी किए

गए। जांच को लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई कोई वसूली सचिव से नहीं हुई। सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद जिला पंचायत द्वारा केवल वसूली के आदेश दिए गए। सचिव पर किसी प्रकार से निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच बालूसिंह गामड ने बताया कि, जब सचिव पर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो अधिकारियों ने सचिव पर पुलिस प्रकरण दर्ज करने की न तो अनुसंसा की, न ही सचिव को हटाया गया, न ही उसका निलंबन किया गया। इससे साफ है कि, सचिव की जिला प्रशासन तक मिलीभगत है और भ्रष्टाचार में सभी लोग लिस हैं।

नही हो पा रहे हैं सरकारी कार्य ,हर कार्य के लिए वसूली

सरपंच-सचिव के बीच आपसी खिंच तान के चलते ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। सरपंच ने बताया कि, सचिव न तो रोज ग्राम पंचायत में आता है न ही ग्रामीणों को कार्य कर रहा है। जन्म,मृत्यु, विधवा-वर्धा पेंशन ,आईडी सुधारना, केवाईसी जैसे सभी कार्य रुके पड़े हैं। सरपंच ने ग्राम पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची भी जनपद के अधिकारी को दी। जिसमें नामजद लोगो से सर्वे के नाम पर 500 रुपये और स्वीकृत मकान के लिए एक हजार से पाँच हजार रुपये सचिव द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत है। इसके अलावा भी सचिव द्वारा शासन की योजना का लाभ देने के नाम पर हितग्राहियों से वसूली की

जाती है। सरपंच ने बताया कि, सचिव को ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड में हेरफेरी करने के उद्देश्य से नहीं हटाया गया। सचिव ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिना जानकारी और बिना कारण 400 से ज्यादा जाबकार्ड डिलीट कर दिए जिससे ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं।

गुमराह करते हैं अधिकारी

उधर भ्रष्टाचार में लिस पाए गए सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ राजेश दीक्षित बचाते नजर आए और कार्रवाई और सचिव को हटाने का अधिकार नहीं होने की बात कहते नजर आए। जब सीईओ दीक्षित से इस विषय में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि, सचिव को हटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है और हमने कार्यवाही करके ऊपर फाइल भेज दी। वर्तमान में ट्रांसफर नीति खुली हुई है इसके तहत सचिव को हटाने हेतु जानकारी दी गई है। तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल द्वारा भी मौके पर पहुँच कर सरपंच और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। देर शाम को जनपद सीईओ के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। सरपंच बालूसिंह गामड ने कहा कि, यदि



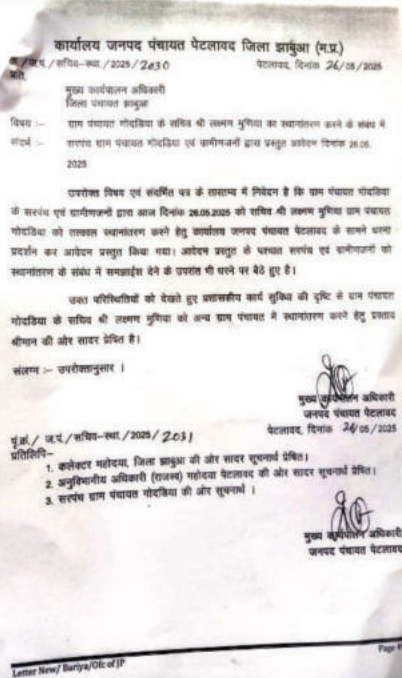
धरने पर बैठे ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीण एवं सरपंच।

सचिव पर कार्रवाई नहीं की जाती तो ग्रामीण फिर से धरने पर बैठेंगे।

आखिर पुलिस प्रकरण क्यों नहीं?

जनपद पंचायत पेटलावद में जारी भ्रष्टाचार की प्रमाणित जानकारी कोई पहली बार सामने नहीं आई है। विकास खण्ड की कम से कम बीस पंचायतो के ऐसे मामलों सामने आ चुके हैं जिसमें लाखों रुपये वसूली के आदेश जिला पंचायत द्वारा

जारी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ग्राम पंचायत की खुली चोरी पकड़े जाने के बाद अब तक किसी भी मामले में पुलिस प्रकरण नहीं बना। मतलब सरकारी राशि में हेराफेरी, भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी कानून के दायरे में न आकर केवल वसूली योग्य बना कर समाप्त किये जा रहे हैं। तथा अपराध की परिभाषा बदल कर रख दी। उधर जांच अधिकारी और प्रतिवेदन तैयार करने वाले अधिकारियों ने आज तक एक



धरने के बाद जनपद पंचायत की और से सचिव को हटाने का पत्र जिला पंचायत को भेजा गया।

भी भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस प्रकरण की अनुसंसा तक नहीं की जिससे उनकी कार्यप्रणाली और मिली भगत के बड़े सवाल खड़े होते हैं।

देव स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की - कटारा

माही की गूंज , पेटलावद।

स्थानीय जनपद पंचायत के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन



अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा अध्यक्षों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें विशेष रूप से पेसा जिला समन्वयक अधिकारी गौरसिंह कटारा उपस्थित रहे। गौरसिंह कटारा के द्वारा 15 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा नियम का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें पेसा नियम के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जैसे ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा पंचायत राज कस्त्याएं, शांति एवं विवाद निवारण समिति, भूमि प्रबंधन, जल संसाधन ,एवं लघु जल संधर योजना, खान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वनोपज,

साहूकारी, एवं सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं व कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण ,तथा विभिन्न हितग्राही योजनाओं में हितग्राहियों का चयन करना आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। ताकि किसी भी तरह से ग्राम सभा अध्यक्षों में जानकारी का अभाव न रहे इसके लिए प्रयास किया गया।साथ ही जिला समन्वयक द्वारा गांव की रूढ़िवादी परम्पराओं एवं जनजाति समाज की आदिम संस्कृति एवं ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित कर उन्हें सुरक्षित रखने के संबंध में ग्राम सभा अध्यक्षों को बताया गया। सीईओ राजेश दीक्षित द्वारा पेसा नियम पर ग्राम सभा अध्यक्षों को विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ब्लाक समन्वयक अधिकारी कैलाश निनामा द्वारा किया गया।

प्री मानसून की बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त

माही की गूंज, खवास। सुनील सोलंकी

शहर सहित ग्रामीण अंचलों में इन दिनों मौसम की प्री मानसून के तहत बारिश होने के कारण आम जन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। मई का पूरा एक माह निकल गया जिससे मौसम काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही प्री मानसून की बारिश तेज आंधी-तूफान से कई ग्रामीण अंचलों में टिन शेड के साथ ही पेड़-पौधे धराशाय हो गए हैं। पानी की बौछार के साथ लगातार तेज हवाओं से ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो ग्रामीण अंचलों में विद्युत व्यवस्था भी चरमरासी गई है जिसकी वजह से कई जगह अंधेरे के साथ ही कम वोल्टेज की समस्या से गुजरना पड़ा,। वही आंधी तूफान के साथ ग्रामीणों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। दिन में गर्मी तो शाम को 3 से 4 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून की गतिविधिया होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। तो वहीं 25 मई से नौतापा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को भी लगातार तेज बारिश के साथ हवा चली जिसके कारण ग्राम पंचायत भामल के अंतर्गत आमली फलिया, रूपापाड़ा व वडलीपाड़ा आदि जगह पर ग्रामीणों के टिन शेड से बने हुए मकान में चढ़ तेज हवाओं के साथ उड़ गए। वही घर के अंदर बंधी



एक भैंस की भी मौत हो गई। लोगों को काफी नुकसान ही झेलना पड़ा। कई जगह पुराने कनेलू वाले मकान भी धराशाय हो गए ग्रामीण भुण्डा पिता दल्ल गखवाल, चंदू डांगी, रमेश पिता गलिया डामर, देवू वाला सिंगाड़, जीतेन्द्र मानसिंह वसुनिया, कमली कमल झोड़ियां, वैसा शैतान झोड़ियां, अनित पिता रमेश डामर, दिनेश हुमला डांगी, मनीष रमेश डामर, गलियां बिरजी डामर, कमल रणजी डांगी, रामचंद्र पल्लू डामोर, बालू पुत्रा वडखिया, आदि लोगों का आधी व बारिश के साथ भारी नुकसान हुआ है। जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आर्थिक मदद मिले इसकी मांग ग्रामीणों ने की।

पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के कारनामे आने लगे सामने

युवक ने एसपी को आवेदन देकर लगाया रुपये वसूलने का गम्भीर आरोप

माही की गूंज , पेटलावद।

विवादित पेटलावद पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा से एक ओर विवाद जुड़ गया है, उनके लाइन अटैच होने के बाद अब धीरे-धीरे उनसे पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रकरण कमजोर करने के नाम से एक युवक से पैसे वसूलने का गम्भीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने 23 मई को पुलिस अधीक्षक झाबुआ को लिखित आवेदन पेश करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। युवक का आरोप है कि, प्रकरण में कमजोर धारा लगाने के नाम पर राशि ली गई। पीड़ित युवक राजेश मालवीय ने पुलिस अधीक्षक को दित् गए आवेदन में पूरी घटना का विवरण देते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजेश मालवीय, जो कि एक बस कंडक्टर है और खामडीपाड़ा गांव के

निवासी हैं, ने बताया कि, रतलाम में प्रदीप बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत रतलाम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद फिर से 10 अप्रैल को विवाद पुनः बढ़ गया , 12 अप्रैल को उन्हें पेटलावद थाना प्रभारी दिनेश शर्मा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और रात भर मुझे थाने की जेल में रखा गया और दिन भर रखकर थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने उनसे थाने में जातिपुचक गालियां दीं, डराया-धमका कर एक लाख रुपये की मांग की। जो पचास हजार में तय हुआ, युवक ने गरीब वर्ग का होने और पैसे नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि मैं, मेरे सेठ से उधार लाकर दूँगा। मामला सेट होने के बाद थाना प्रभारी दिनेश शर्मा द्वारा कम धारा लगाकर चालान पेश कर एसडीएम कोर्ट से मेरी जमानत हुई और

मुझे छोड़ दिया गया।

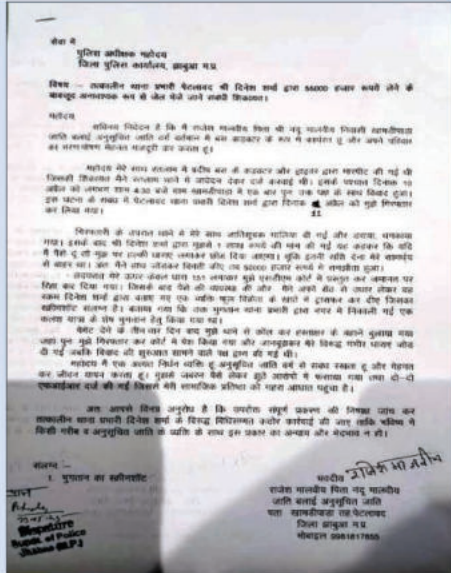
सेठ से पैसे लेकर ,शर्मा के बताए नम्बर पर भेजे पैसे युवक ने बताया कि, सेठ के पास से पचास हजार रुपए उधार लेकर आया और टीआई साहब ने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि, इस नंबर पर पेमेंट डाल दो तो मैंने वह पेमेंट उस नंबर पर डाल दिया। चौकाने वाली बात यह है कि, पैसा देने के पंद्रह दिन बाद एक बार फिर राजेश को हस्ताक्षर के बिना दोबारा थाने बुलाकर गिरफ्तार किया गया तथा जबरन चार अन्य नाम जोड़ दिए गए और उन पर गंभीर धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश किया गया।

राजेश का आरोप है कि, यह सब जानबूझकर किया गया ताकि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है



पीड़ित राजेश मालवीय।

। फिलहाल मामले में क्या कार्रवाई हुई और इसकी जांच किस स्तर पर हो रही है इसकी जानकारी नहीं मिली हैं। मामला दलित युवक से जुड़ा है इसलिए पुलिस को मामला गम्भीरता से लेना होगा।



पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत की प्रत।

पंथ संचलन में

कदमताल करते हुए

स्वयंसेवक समूह ने सभी

को किया आकर्षित

माही की गूंज ,पेटलावद।

मातृहस्त भोजन की अनूठी पहल कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग(व्यवसायी) में 206 परिवारों ने मिलाकर 400 संघ के अधिकारी, प्रशिक्षक, शिक्षक व प्रबंधकों को एक खुले मैदान में बैठ कर परिवारसह भोजन करवाया।

मातृहस्त भोजन की परिकल्पना में 15 दिन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों को घर जैसा माहौल प्रदान करना और सामाजिक समरसता के भाव को दृढ़ करना रहा। जिसमें वर्ग स्थल पर खुले मैदान में 206 ब्लाक बनाकर हर ब्लाक में एक एक परिवार और उनके साथ दो स्वयंसेवक ने साथ बैठकर भोजन किया। जब यह संपूर्ण दृश्य जिसने भी देखा उसने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। इस मातृहस्त भोजन में परिवार अपने साथ घर से ही बैठने के लिए दरी से लेकर भोजन की सभी आवश्यक सामग्री को लेकर आते है और सामूहिक रूप से परिवारसह भोजन करवाते है। जिसमें परिवारजन भी साथ में भोजन करते है। 206 परिवार के 480 सदस्य व वर्ग के 400 स्वयंसेवक एक साथ एक स्थान पर बैठ कर परिवारसह भोजन का आनंद लिया। मातृहस्त भोजन के पश्चात स्वयं सेवकों के द्वारा प्रति एक परिवार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दो- दो पौधे प्रदान किये गये।

पंच परिवर्तन का संकल्प

सामाजिक समरसमता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक अनुशासन इन पंच परिवर्तन पर संघ अपने शताब्दी वर्ष में कार्य कर रहा है। जिसमें सभी हिंदू भाई बहनों को जातिवाद से उपर उठ कर सामाजिक समरसता के भाव जागृत करने की प्रेरणा दी जा रही है। जिसके तहत सभी में समानता का भाव जागृत हो कर्म अलग अलग हो सकते है पर सभी हिंदू एक है। उक्त बात मातृहस्त भोजन के लिए आए 206 परिवारों को बौद्धिक देते हुए मालवा प्रांत सह कार्यवाह रघुवीरसिंह सिंसीदिया ने कही।

इस अवसर पर रतलाम विभाग सह कार्यवाह और वर्ग प्रबंध पालक आकाश चौहान भी उपस्थित रहे। रघुवीरसिंह सिंसीदिया ने कहा कि, हमें सबसे पहले कुटुम्ब प्रबोधन की आवश्यकता है। हमारी पुरातन परंपरा परिवार के एक साथ भोजन करने, बच्चों में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और परिवार में एक जुटता लाना होगी। पश्चिमी संस्कृति व्यक्ति प्रधान है पर हमारी भारतीय संस्कृति परिवार प्रधान है। हम परिवार को महत्व देते है। रघुवीर सिंह सिंसीदिया ने बताया कि नागरिक अनुशासन जरूरी है। जिस प्रकार हम सरकार से अपेक्षा रखते है। इसी प्रकार हमारे कर्तव्य भी होते है। हमें समय पर कर चुकाना, टैफिक नियमों का पालन करना, सरकारी संपत्ती को नुकसान नहीं पहुंचाना,स्वच्छता का ध्यान रखना आदि बातों में नागरिक अनुशासन लाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढेगा। इसके पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों के द्वारा पत्र संचलन निकाला गया।



संपादकीय

मनरेगा को टेगा

श्रमिकों को घर के पास ज़िंदगी के अवसर उपलब्ध कराने के लिये शुरु की गई मनरेगा से जुड़ी धांधलियां



अकसर उजागर होती रहती हैं। ताजा घटनाक्रम में ठेकेदारों व निहित स्वार्थी तत्वों की सांडगाट को ऑनलाइन भुगतान के जरिये बेनकाब किया गया, जिसमें लाखों फर्जी श्रमिकों को भुगतान के मामले उजागर हुए। निश्चित रूप से ये घटनाएं हमारे समाज में यें-केन-प्रकारेण धन अर्जन की लालसा को ही उजागर करती हैं। साथ ही नैतिक मूल्यों के पतन की गाथा भी कहती हैं। ऐसे ही पंजाब के गुरदासपुर के गाजीकोट गांव में उजागर हुआ कार्टून घोटाला एक हास्यास्पद, लेकिन बेहद परेशान करने वाला उदाहरण है कि भ्रष्टाचार के लिये किस हद तक गिरा जा सकता है। कथित तौर पर पंचायत सदस्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत मजदूरों की उपस्थिति को फर्जी ढंग से दर्शाने के लिये एक सरकारी स्कूल के गेट पर बनाए गए कार्टूनों का सहारा लिया। इन चित्रों के साथ लाभार्थियों की तसवीरें मजदूरी के सबूत के तौर पर अपलोड की गईं। विडंबना देखिए कि उस काम के लिए भुगतान लिया गया जो कभी किया ही नहीं गया था। दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक योजना के तहत स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग्स बनायी थी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया जा सके। लेकिन शातिर लोगों ने उसका दुरुपयोग मनरेगा में घोटाले को अंजाम देने के लिए किया। निश्चय ही यह हमारे समाज में कुशासन, नैतिक पतन और तकनीकी खामियों की घातक जुगलबंदी को दर्शाता है। इस घोटाले का एक बेराम पहलू यह भी था कि कथित तौर पर पंचायत अधिकारियों के करीबी दो भाइयों को कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह काल्पनिक काम के लिये बेशर्मी से भुगतान कर दिया गया। यही वजह है कि मनरेगा के तहत वित्तीय आवंटन व योजना के क्रियान्वयन को व्यावहारिक बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्य व अदृश्य बेरोजगारी दूर करने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है।

निःसंदेह, लंबे अरसे से मनरेगा के तहत मजदूरी देने में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। यह केवल पंजाब के गुरदासपुर का मामला ही नहीं है, हाल के वर्षों में पूरे देश में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले उजागर होते रहे हैं। कुछ दिन पहले, गुजरात में एक राज्य मंत्री के बेटों से जुड़े 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में फर्जी प्रोजेक्ट और अन्य धांधलियां सामने आई थीं। मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान किया गया। कुछ माह पूर्व कर्नाटक में, पुरुष श्रमिकों ने महिला जॉब कार्डधारकों का रूप धारण करने के लिये साड़ी पहनी थी। ये उदाहरण ग्रामीण आजीविका और सम्मान को बनाये रखने के लिये बनायी योजना का मजाक उड़ाने वाले हैं। दरअसल, ऐसे घोटालों का उजागर होना अंततः कल्याणकारी कार्यक्रमों में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। सही मायनों में ऐसी धांधलियों से वास्तविक लाभार्थियों के हितों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभाव संगठित भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। निस्संदेह, ऐसी धांधलियों को दूर करने के लिये गहन तथा प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। दरअसल, तसवीरों में धांधली और उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी रोकने के लिये डिजिटल उपकरणों के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए। साथ ही एक पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था भी कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा दोषी अधिकारियों तथा बिचौलियों के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। ग्रामीण गरीबों को सांकेतिक रोजगार और खोखले वायदों से कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। निश्चय ही वे सम्मानजनक पारिश्रमिक पाने के हकदार हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनरेगा ने देश में अंतर्राज्यीय प्रवास को कम किया है। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को भी बढ़ाया है। काम की तलाश में शहरों की ओर जाने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। खासकर कोरोना संकट में जब ग्रामीण महानगरों से पलायन करके बड़ी संख्या में गांवों की तरफ लौटे तो इस योजना ने जीवनदायिनी भूमिका निभाई।

ऑपरेशन सिंदूर के निष्कर्षों से सीखें सबक

ऑपरेशन सिंदूर का अचानक यू खत्म होना एकदम अप्रत्याशित था दुवास्तव में, यह किसी परीक्षा-पत्र में ‘पाठ्यक्रम से इतर’ आए सवाल की तरह रहा! हालांकि, अच्छा हुआ कि पूर्ण पैमाने का युद्ध टल गया और उम्मीद करें कि संघर्ष विराम का आगे उल्लेघन नहीं होगा। भले ही सशस्त्र बल हमारी सीमाओं पर सतर्क नज़र रखे हुए हों, तथापि कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो समीक्षा के रूप में निकाले जा सकते हैं।

सर्वप्रथम, मौजूदा सेना के रिवायती त्रि-सेवा तंत्र ने रणभूमि कमान के बिना भी काम कर दिखाया है। इसलिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए नरसंहार और 7 मई को आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद तीन दिन चले हमलों की शुरुआत होने के बीच की अवधि में थल और वायुसेना ने बड़ी विशेषज्ञता से संयुक्त योजना की रूपरेखा तय कर इनके परिणाम दिए। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले निरंतर, तीव्र और सघन थे और हमारी प्रतिक्रियाएं भी समान रही, लगभग सभी पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र (यूएवी, मिसाइल, सशस्त्र और बिना हथियार वाले ड्रोन) सफलतापूर्वक गिरा लिए गए, इसका श्रेय भारतीय वायुसेना के स्वदेश विकसित एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) को जाता है, जो सभी सैन्य और नागरिक राडार जनित समग्र सूचना को एकीकृत स्क्रीन पर सश्लेषित कर दिखा देता है। यह प्रणाली लक्ष्यों से पैदा होने वाले खतरों का इलेक्ट्रॉनिक आकलन करके, युद्ध नियंत्रक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जो भी हथियार प्रणाली सबसे उपयुक्त हो, उसका इस्तेमाल कार्रवाई करने का आदेश देती है।

दूसरा, चार दिनों तक चले आपसी टकराव मुख्यतः पूरी तरह से न सही, हवाई माध्यम से चोट पहुंचाने वाले रहे। यह टकराव एक ऐसे सघन वायु रक्षा प्रणाली से

लैस इलाके में हुए, जहां दोनों पक्ष वार-प्रतिवार की हवाई लड़ाई लड़ रहे थे, यह स्थिति इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में पश्चिमी ताकतों द्वारा और गाज़ा एवं लेबनान पर इस्राइलियों द्वारा की गई हवाई बमबारी से उलट थी, जहां उन्हें अपने अभियानों में विरोधियों के हवाई हमला निरोधक उपायों का सामना नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक है

युद्ध में नुकसान भी होता है और यह संघर्ष की एक अनन्य प्रकृति है कि आक्रामक पक्ष को कुछ नुकसान झेलना ही पड़ता है, निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना इसका भी आलोचनात्मक विश्लेषण करेगी।

अब उपलब्ध फोटोग्राफिक साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत के यूएवी और मिसाइलों के हमले बहुत प्रभावी रहे, और यह तथ्य है कि पाकिस्तान भर में फैले उसके ग्यारह फंटलाइन एयरबेसों पर भारतीय वायुसेना ने करारी चोट की है और यह हमारी पहुंच और हथियारों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। हालांकि, भारतीय वायुसेना के स्काइनों की घटती संख्या और वायु-शक्ति के बारे में काफी खबरें आती रही हैं और चूंकि हमारी सीमाएं आगे भी सक्रिय रहेंगी, इसलिए भारतीय वायुसेना की प्रहारक क्षमता बनाए रखने पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हथियार प्रणाली, एंकिप्टेड संचार और प्रहारक क्षमता जैसे कि एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरियल प्लाइंट रिफ्यूलर और अत्याधुनिक अस्त्रास्त्र जैसी प्रणालियों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम विश्लेषण में यह याद रखना चाहिए कि यह एक अन्य उदाहरण रहा, जब वायु शक्ति की

है, इसकी बढ़िया कारगुजारी ने स्वदेशी हथियारों का महत्व उजागर किया है। गौरतलब है कि यह क्षमता डीआरडीओ और निजी क्षेत्र के सम्मिलित उद्यम से बनी है और वास्तव में यह बहुत उत्साहजनक है। ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम की प्रचुर उपलब्धता रहने के पीछे क्षेत्रीय कमानों के वाइस चीफ और कमांडर-इन-चीफ को दी गई अपातकालीन शक्तियों का परिणाम भी हो सकता है।

वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा डिजाइन की गई कम दूरी की एंटी-एयरक्राफ्ट प्रणाली, सरफेस-टू-एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन (एसएएमएआर) के रूप में अपने ही संस्थानों में विकसित किए स्वदेशी अस्त्र बहुत काम आए। यह एसएएमएआर हमने सरफेस-टू-एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली रूस निर्मित आर-

73 और आर-27 एयर टू एयर मिसाइलों का नवीनीकरण करके पाया है (वरना इससे पहले उनका जीवनकाल समाप्त होने पर कबाड़ के रूप में खुर्द-बुर्द करना पड़ता था)। यह बताता है कि हमारे अपने संस्थानों में तीक्ष्ण बुद्धि दिमाग हैं, जिन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। यहां पर, उन अथक वायु रक्षा गनर्स (जिन्होंने लगातार एल-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे रिवायती शस्त्रास्त्र

चलाए) और बीएसएफ के जवान (जिन्होंने एंटी-यूएवी सिस्टम को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल किया) द्वारा किए गए अद्भुत काम की सराहना करना लाजिमी है।

चौथा, एक आम आदमी जिसकी सूचना तक पहुंच केवल मीडिया से मिले समाचारों तक थी, लगता है इस बारे में नागरिक-सैन्य-राजनयिक तंत्र ने अच्छा काम किया है। एक ईमानदार

मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है कि क्या नवीनतम स्थिति युद्ध विराम समझौते की ओर ले जाने वाली घटनाओं और युद्ध विराम के स्वीकार करने से पहले मिले आश्वासनों के अनुरूप है। इसका उत्तर इस एक अकेले प्रश्न के उत्तर में निहित होगा, क्या हर बार आतंकवादी कार्रवाई को प्र इस किस्म की गतिज कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी? हालांकि पाकिस्तान को याद रहे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा होने पर बदले में दंडात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।

पांचवां, क्या युद्ध विराम इस बात का संकेत है कि हम लगभग पूर्ण युद्ध की कगार पर पहुंच चुके थे? कुछेक प्रश्नों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं, जिन्होंने अपने निर्दयी नरसंहार से यह सब शुरू किया था? क्या यह



एवर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर

समझौते में आपसी समस्याओं का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के जरिए निकालने की बात कही गई है, इसलिए युद्ध विराम की घोषणा करते समय अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बयान का यह भाग कि ‘सभी मुद्दों पर तटस्थ जगह पर चर्चा करें’, इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह करना फौरी तौर पर जरूरी है क्योंकि ‘सभी मुद्दे’ शब्द से समस्याओं का पिटारा खुल सकता है।

अंत में, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का जवाब चाहिए कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ वाली प्रणाली, जिसके लिए यह टकराव पहली परीक्षा रहा, क्या उसने वह काम कर दिखाया जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। सैन्य मिशनों की योजना वास्तव में कौन बना रहा था और ‘युद्ध’ को अंजाम किसने दिया दू एकीकृत रक्षा संगठन ने या फिर सेना और वायु सेना के क्षेत्रीय कमान मुख्यालयों के कमांडर-इन-चीफ इन कार्रवाइयों का संचालन कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे उच्चतर रक्षा संगठन तंत्र (थिएटराडिजेशन) के फिलहाल जारी पुनर्गठन में एक अमूल्य योगदान होगादु युद्ध की भंडी से तपकर निकले अनुभव से ज्यादा बढ़िया सबक दुबारा मिलना असंभव होगा।

वास्तव में, यह करना उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को एक उचित श्लाघा होगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया।

फैंसी ड्रेस की दुकान बन गया पाकिस्तान

पाकिस्तान की खबरें देखें, तो सवाल उठता है कि यह कामेडी है या ट्रेजेडी। यह देश है या ड्रामा है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती हैं कि शर्म आती है यह सोचकर भी कुछ सालों पहले यह भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, कैसे-कैसे उच्चकोटि की बेवकूफियां जहां से निकल रही हैं, वो कभी हिंदुस्तान था।

फैंसी ड्रेस की दुकान में एक बंदा निकलता है-भिखारी के भेष में- दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे, दे दे तेरे बच्चे जीयेगे, दे दे चार दिन से रोटी नहीं खायी है, भिखारी रो रहा है, भिखारी करतब दिखा रहा है। भिखारी को दो चार रुपये मिल जाते हैं। भिखारी मस्त होकर सो जाता है।

फिर भिखारी फैंसी ड्रेस की दुकान में घुसकर नये भेष में आ जाता है-अबकी बार फुल राय में फौजी ड्रेस में कह रहा है मार दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, एटम बम मार दूंगा।

फौजी ड्रेस वाला बंदा अंदर घुस जाता है, अब वह नेताई ड्रेस में आकर कह रहा है कि

इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया की सांस बंद कर देंगे।

पाकिस्तान एक फैंसी ड्रेस की दुकान है, वही बंदा भिखारी हो जाता है, वही फौजी हो जाता है, वही नेता हो जाता है। मुल्क है या फैंसी ड्रेस की दुकान।

पाकिस्तान, कामेडी ड्रामा भी है। जनरल साहब पिट

गये, फिर वह प्रमोशन पा जाते हैं और वह फील्ड मार्शल हो जाते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हर युद्ध हारा है, और हर युद्ध के बाद



जनरल प्रमोशन पा जाता है। इसलिए तो यह कमाल का मुल्क है।

दरअसल, पाकिस्तान एक बिगड़ैल

बच्चा है, जो समझता है कि उसे पालना दुनिया की जिम्मेदारी है।

उस बिगड़ैल बच्चे का जिम्मा सिर्फ रायता फैलाने का है। दुनिया भी परेशान हो गयी है, कैसे झेलें इस बिगड़ैल बच्चे को। बच्चा सुधरने की तैयार नहीं है।

बच्चा बड़ा होने से इनकार करता है। बच्चा कुछ करता नहीं है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान से सिर्फ तीन तत्व जाते हैं बाहर, एक तो गंधे जा रहे हैं चीन।



आलोक पुराणिक

भिखारी जा रहे हैं अरब देशों में, और आतंकी आ रहे हैं भारत। इन तीनों कामों में ज्यादा कमाई नहीं है तो पाकि स्तान भीख पर उतर आता है। भीख मांगकर फिर धमकी पर उतर आता है। उसका क्या होगा?

जो वही होगा, जो होता आ रहा है, फैंसी ड्रेस की दुकान और लगातार बढ़ती जायेगी। भीख और बढ़ती जायेगी। इंसान हो या देश अगर कोई खुद को गंभीरता से नहीं लेता, तो कोई और भी गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तान अगर देश होता, तो जरूर समझ लेता। पर पाकिस्तान देश कहां, फैंसी ड्रेस की दुकान है जो।

जासूसी के तकड़जाल पर कानून की निगाहबानी

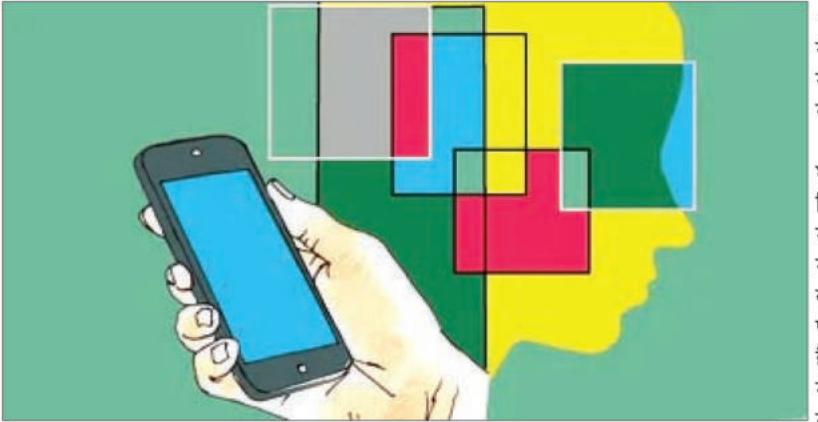
हाल ही में हुए सशस्त्र संघर्ष के बाद भारत में पाक खुफिया एजेंसियों के जासूसों और मुखबिरों के नेटवर्क पर कार्रवाई अपरिहार्य थी। यू-ट्यूबर, यायावर, शिक्षाविद, अपराधी और छेड़े व्यवसायियों सहित एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों को दुश्मन देश की गुप्त सेवाओं के साथ सदिग्ध सम्बन्धों के चलते गिरफ्तार किया गया है। सम्भव है कि इनमें से अधिकतर व्यक्ति धन प्राप्ति, वीजा पाने और प्रायोजित विदेश यात्राओं की खातिर अथवा अन्य प्रलोभन के वशीभूत होकर विदेशी एजेंटों के जाल में फंस गए हों।

समय के साथ जासूसी के दायरे और विधाओं में बदलाव आया है और इसके आयाम अधिक व्यापक और जटिल हो गए हैं, जिसमें विभिन्न तकनीक पर आधारित, कार्यप्रणाली तथा तरह-तरह के लक्ष्य शामिल होते जा रहे हैं। प्राचीन युग में राजाओं के मुखबिर जानकारी एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गुप्त रूप से घूमते थे। अधीनस्थ रियासतों के षड्यंत्रों तथा महल की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए भी राजाओं द्वारा गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। आधुनिक सूचना क्रांति के दौर में गुप्त जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रियाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। इनमें साइबर हमलों और आतंकवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सम्भावित खतरों की पहचान करना, विरोधियों की सैन्य क्षमताओं को परखना और सैनिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के साथ-साथ व्यापारिक रहस्यों, बाजार के रुझान और प्रतिस्पर्धियों की जानकारी से सम्बन्धित मामलों पर आर्थिक जासूसी शामिल है। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों एवं भू-राजनीति से जुड़े मसलों की निगरानी शामिल है।

औद्योगिक क्रांति के बाद, आधुनिक राज्य की अवधारणा विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक जटिल विश्व-व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था के लिए आवश्यक रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक महत्व को जानकारी एकत्रित करने के लिए

पारम्परिक मानव-केन्द्रित गुप्तचर प्रणाली बहुत कम उपयोगी रह गई है। इसके लिए सिग्नल इंटेलिजेंस, वायर इंटरसेप्शन, फोटोग्राफी, उपग्रह इमेजरी और साइबर निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी और अमूर्त परिसम्पत्तियों पर आधारित तौर-तरीकों से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण गुप्तचर संस्था की जरूरत आन पड़ी है। कुत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर उपकरणों का उपयोग सटीक और सम्यक ‘सॉफ्ट इंटेलिजेंस’ एकत्रित करने और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिकी पर आधारित प्रणालियों को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। विरोधियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए हाईवेयर को हैक करना और सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना आम बात हो गई है। साइबर जासूसी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक-संचार माध्यमों को बाधित करके उनसे प्राप्त सिग्नलों का विश्लेषण करने के लिए ‘सिग्नल इंटेलिजेंस’ लोकप्रिय हो रही है। ‘इमेजरी इंटेलिजेंस’ तकनीक का उपयोग करना, जिसमें उपग्रह और ड्रोन, हवाई टोही यंत्रों द्वारा डिजिटल फोटोग्राफी शामिल है, अब कोई रहस्य नहीं रह गया है।

हालांकि, व्यक्तियों, संगठनों और दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अन्दर के भेदी लोगों को अपने साथ मिलाकर लक्षित संस्थान के अन्दर घुसपैठ करके पारम्परिक निगरानी के तरीके गुप्त एजेंसियों द्वारा अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दुश्मन की सूचना एकत्र करने वाली इकाइयों को बाधित और भ्रमित करने, देश के राजनीतिक हितों के रक्षार्थ तथा ‘डिप स्टेट’ के नापाक मंसूखों पर पानी फेरने के लिए भी जासूसी आवश्यक है। हितधारक, प्रतिद्वंद्वी की गुप्तचर



अथवा प्रभावित करते हैं। कुछ हालिया गिरफ्तारियों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

दुनियाभर की सरकारों द्वारा जासूसी और ‘डिप स्टेट’ के प्रचार के खतरों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र विकसित किया जाता रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों और सूचनाओं के प्रकटीकरण को रोकने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा वर्ष 1889 में भारतीय आधिकारिक गोपनीयता

अधिनियम (आईओएस एक्ट) अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस कानून को और मजबूत किया गया और परिणामस्वरूप 1904 में आईओएस एक्ट में संशोधन किए गए।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अंग्रेजों को सैन्य रहस्यों और प्रतिष्ठानों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा ‘आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923’ (ओएस एक्ट) पारित किया गया। जिसमें शासन के लिए आवश्यक गोपनीयता के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था।

ओएस एक्ट जासूसी को अपराध घोषित करता है। जासूसी की परिभाषा में किसी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करना या स्कैच और नोट बनाना या किसी सरकारी दस्तावेज या सूचना को प्राप्त करके उसे अवांछनीय तत्वों तक पहुंचाने के कार्य को शामिल किया गया है, जो किसी दुश्मन के लिए उपयोगी साबित हो सकता हो या जो भारत की संप्रभुता और अखण्डता एवं विदेशों के

साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रभावित कर सकते हो। यहाँ तक कि किसी विदेशी गुप्तचर के साथ मात्र सम्पर्क रखना भी ओएस एक्ट की धारा 4 में अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

गोपनीयता, सरकारों के कामकाज में अन्तर्निहित है। किसी भी सरकारी सूचना को जान-बूझकर प्रकट करना या किसी लोक सेवक के कब्जे में स्थित आधिकारिक दस्तावेज को किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करना ‘ओएस एक्ट’ के अन्तर्गत अपराध है जिसमें 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।

कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि ‘ओएस एक्ट’ केवल सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के इर्द-गिर्द घूमने वाले अवांछित व्यक्तियों और लोक सेवकों के अतिवेकपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए ही पर्याप्त है, यह दुश्मन के गुप्तचरों से राष्ट्रीय सुरक्षा को दरपेश गम्भीर खतरों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। तबानुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) में एक नई धारा 152 जोड़ी गई, जिसके अन्तर्गत सशस्त्र विद्रोह को भड़काना या अलगाव को बढ़ावा देना और वित्तीय साधनों या अन्य किसी भी प्रकार से भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरों में डालना आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत की सुरक्षा को खतरों में डालने वाली भ्रामक जानकारी फैलाना और बेबुनियाद प्रचार करना अथवा उन्हें प्रकाशित करना, बीएनएस की नई जोड़ी गई धारा 197(1)(डी) के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की कैद से दण्डनीय अपराध घोषित किया है।

निःसंदेह, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की एकता और अखण्डता, सार्वजनिक शांति और सामाजिक सद्भाव सर्वोपरि हैं और इन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही, अभिव्यक्ति की आजादी या अलगाव की खातिर जासूसी से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कानूनी शक्तियों के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना को रोका जा सके।



के. पी. सिंह

वकील की मौत के 40 वर्ष बाद हीबानामा के आधार पर नामांतरण का मामला चर्चा में

मुख्य नगर परिषद अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच की मांग

माही की गूंज, आष्टा।

नगर परिषद आष्टा ने एक वकील के बेशकीमती मकान को उनकी मौत के 40 वर्ष बाद हीबानामा के आधार पर अन्य लोगों के नाम नामांतरण कर दिया। जिसकी शिकायत आष्टा में वकील रहे स्वर्गीय खलील एहमद के पुत्र सईद एहमद एवं रईस एहमद ने लोकायुक्त संगठन भोपाल, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, कमीशनर भोपाल संभाग एवं कलेक्टर सीहोर को कर आष्टा नगर परिषद के मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की मांग की है। शिकायतकर्ता सईद एहमद एवं रईस एहमद निवासी हाथीखाना आष्टा ने बताया कि उनके पिता स्व. खलील एहमद की मालिकयत एवं कब्जे का करीब दो करोड़ रुपये की कीमत का मकान सिफंदर बाजार आष्टा में है, जिसका फर्जी हीबानामा की कहानी के आधार पर नगर परिषद आष्टा ने नामांतरण मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद बिलाल पुत्रगण मोहम्मद इलियास निवासी काजीपुरा के नाम कर दिया। इस मकान पर सईद एहमद एवं रईस एहमद ही बतौर मालिक वकील खलील एहमद की मृत्यु दिनांक 25.5.1988 के बाद से काबिज हैं तथा समय

समय पर वे नगरपालिका का टेक्स भी जमा करते रहे हैं, परंतु गत कुछ माह पहले उनके पिता की इस मकान को हड़प कर जाने की नियत से फर्जी हीबानामा की कहानी बनाकर तथा झूठे गवाह हाजी शेखूद्दीन पिता कमरूद्दीन निवासी सिंगारचोरी, तह0 आष्टा, जिला सीहोर, सगीर खाँ पिता मासूम खाँ निवासी सिंगारचोरी, तह0 आष्टा एवं खुशीलाल पिता सालगराम निवासी इंदिरा कालोनी, आष्टा को बनाकर नगरपालिका आष्टा के मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना के साथ साठगांठ कर दिनांक 21.8.2024 को नामांतरण मोहम्मद जुबेर,



मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद बिलाल पिता मोहम्मद इलियास के नाम से कथित नामांतरण दिनांक 21.8.2024 को कर दिया, जबकि उन्होंने मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना को दिनांक 15.7.2024 को ही लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी, पुनः दिनांक 20.8.2024 को मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना को लिखित आपत्ति नामांतरण नहीं करने बावत् दी। इस महत्वपूर्ण नामांतरण प्रकरण का आपत्ति इश्तेदार अनजान ने अखबार में प्रकाशित करवाया ताकि किसी को जानकारी नहीं मिल सके।

जबकि नियम अनुसार नामांतरण का इश्तेहार आपत्ति आमंत्रण का प्रकाशन सबसे ज्यादा वितरित होने वाले अखबार में किया जाना था। मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना ने शपथपत्र दिनांक 19.7.2024 खलील मियाँ की कोई संतान नहीं थी का परीक्षण किए बिना तथा शिकायतकर्ता सईद एहमद, रईस एहमद को हीबानामा के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बिना नामांतरण प्रकरण को अध्यक्ष को भेज दिया तथा एकपक्षीय विधिक अभिमत भी पूर्व से नगर परिषद के नियुक्त वकील दिनेश भूतिया की जगह नए वकील नीलेश शर्मा की नियुक्त कर एकपक्षीय विधिक अभिमत लिया। सईद एहमद और रईस एहमद ने इस कथित विवादित नामांतरण को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर के समक्ष अपील भी की है तथा राजेश सक्सेना मुख्य नगर परिषद अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच करने की मांग की है क्योंकि यदि हमारे पिता खलील अहमद का कोई हिबानामा होता तो उसे 40 साल तक छुपाकर क्यों रखा गया। शिकायतकर्ता सईद एहमद का कहना है कि, हमारे पिताजी स्वर्गीय खलील एहमद काफी पढ़े लिखे थे वे यदि अपने मकान का हिबा करते तो वो लिखित या रजिस्टर्ड हिबा करते। नगर पालिका के सी ओ की मिलीभगत से हमारे मकान का गलत नामांतरण किया गया है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्यपदेश बटालियन एन.सी.सी., मंदसौर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 26 मई से 04 जून तक मंदसौर में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नीमच और मंदसौर के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, करियर आदि विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कैडेट्स को इन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। यह शिविर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जहाँ उन्हें न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामूहिक कार्य तथा कठिन समय में दृढ़ता के साथ मुकाबला करने का और अपनी भूमिका को भी समझने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शिविर में कैडेट्स फौजी जीवन से परिचित होंगे और राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे हथियारों को चलाने खेलने और जोड़ने, मैप रीडिंग, और विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षणों का अभ्यास करेंगे। शिविर में खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएँगी, जिला प्रशासन की ओर से इस शिविर के लिए यथा सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। कमान अधिकारी ने बताया कि इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले छात्र सैनिकों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा हर कैडेट राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है और अपनी सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है, युद्ध में कैडेट सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करने को उत्सुक हैं। कर्नल ने यह भी कहा कि हमारे कैडेट्स समाज में हमारे सदेशवाहक हैं और राष्ट्र की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैयार हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स नागरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका को समझेंगे और इसे निभाने के लिए तैयार किये जाएंगे। यह शिविर युवा मनों को अनुशासन, नेतृत्व और सेवा के मूल्यों से सशक्त करने का प्रयास है, इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण है जो समृद्धि के साथ-साथ संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व से परिपूर्ण हो।

16 जिलों के किसान बड़े आंदोलन की तैयारी

माही की गूंज, मंदसौर।

इस साल मानसून के समय से पहले आने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 8-10 जून तक आएगा। ऐसे में किसान चिंतित हैं, क्योंकि खेतों में मृग की आधी फसल पक चुकी है। मृग दाल 50 फीसदी पक चुकी है और बाकी दालों को पकने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में किसानों को चिंता है कि कहीं उनकी दो महीने की मेहनत बारिश में बर्बाद न हो जाए। दूसरी ओर, जिन किसानों ने मृग की फसल काट ली है, वे मृग को सुरक्षित रखने को लेकर चिंतित हैं। अगर एमएसपी पर खरीद की तारीख घोषित नहीं होती है, तो परेशान किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 16 जिलों में किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं।

किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं

किसान स्वराज संगठन के प्रदेश



सचिव गजेंद्र जाट ने कहा कि, अभी तक सरकार की ओर से मृग खरीद को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कृषि मंत्री भी इस मुद्दे पर चुप हैं। यदि सरकार मृग खरीद की तिथि तय नहीं करती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के 16 जिलों के किसान सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि 28 मई को किसान नर्मदापुरम में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें भैरोंदा क्षेत्र सहित कई स्थानों से किसान पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं, किसान स्वराज संगठन भी 30 मई को भैरोंदा में किसानों की बैठक कर ट्रैक्टर रैली निकालने पर चर्चा करेगा। किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए किसान अब आर-पार की लड़ाई

लड़ने को तैयार हैं।

6 जून को मंदसौर से होगी आंदोलन की तैयारी

जाट ने बताया कि, 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। इस दिन यहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की प्रदेशाध्यक्ष गीता मीना सहित कई अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारी जुटेंगे। यहीं से पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जाट के अनुसार यदि सरकार मृग की खरीदी नहीं करती है तो हजारों किसान सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और चक्का जाम करेंगे। 43 हजार हेक्टेयर में मग लगाया गया बता दें कि, इस साल इस क्षेत्र में

43 हजार हेक्टेयर में मग लगाया गया है। इस साल अनुकूल मौसम के कारण मग उत्पादन में भी सुधार हो रहा है। जागरूक किसानों द्वारा कई नई किस्में लगाई गई हैं, जिनसे प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उत्पादन मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 26,022 किसानों से 71,734 मीट्रिक टन मग खरीदा गया था, जो वर्ष 2022 की तुलना में 2,726 मीट्रिक टन अधिक था। प्रति किसान मग खरीद का लक्ष्य 12 क्विंटल रखा गया था, फिर भी रिकॉर्ड खरीद हुई। मग खरीद के बदले किसानों को 613 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। लेकिन इस साल मग खरीद को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

बिहार एसटीएफ की गाड़ी पलटी, दो जवानों की मौत और चार घायल

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में दिल्ली-मुंबई आठ लेन एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह गुजरता जा रही बिहार एसटीएफ की गाड़ी अनियंत्रित होकर पटल गई। इस हादसे में एसटीएफ के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि चार पुलिसकर्मियों घायल हुए हैं, जिन्हें रतलाम तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

घायलों में एक की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें तत्काल इंदौर रेफर किया गया। वहीं, तीन घायलों को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन तीनों को भी इंदौर रेफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से चर्चा कर उपचार की जानकारी ली।

रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बिहार एसटीएफ के जवान गया से स्कॉर्पियो वाहन (कार) में बैठकर एक अपराधी को पकड़ने के लिए गुजरता के गांधीधाम जा रहे थे। बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ईसरथूनी के समीप स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक बीआर-02 पीके 3135 अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) मुकुंद मुरारी और आरक्षक (कॉन्स्टेबल) विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार और तीन कॉन्स्टेबल जीवधारी कुमार, मिथिलेश पासवान व रंजन कुमार कुमार घायल हुए हैं। प्रत्यदर्शियों ने बताया कि तेज गति के चलते वाहन अनियंत्रित होने के बाद पलटी खा गया। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घायल आरक्षक रंजन कुमार ने बताया कि मैं पीछे सोया हुआ था। पता नहीं कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। जब गाड़ी रुक गई तब बाहर निकलकर देखा तो हादसा हो गया था। घायल मिथिलेश पासवान ने बताया कि हम गया से गांधीधाम जा रहे थे। सीक्रेट ऑपरेशन था। एक्सप्रेस-वे पर रतलाम से आगे गाड़ी अनब्रैकेस होने के कारण एक्सीडेंट हो गया।

मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। आज भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ताल और आलोट क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए ग्राम मंडवल में स्थित श्री कृष्ण टी स्टाल रेस्टोरेंट एंड किराना स्टोर का निरीक्षण कर बेसन,चावल,चायपत्ती के नमूने लिए गए,ग्राम आबूपुरा स्थित श्री स्वार्सियां मावा भट्टी से मावा एवं दूध के नमूने लिए गए। इसी प्रकार मेन रोड आलोट स्थित स्वागत ट्रेडर्स से रवा के नमूने लिए और वंदन ट्रेडर्स से देशी घी के नमूने लिए गए तथा बडौद नाका आलोट स्थित श्री खाट्रय्याम टी स्टाल एवं रेस्टोरेंट से बेसन एवं मिठाई के नमूने लिए गए। विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर सभी दुकान संचालकों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और गुणवातायुक्त खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए। लिए गए सभी नमूने जांच हेतु भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर महिलाओं के लिए हुए विशेष कार्यक्रम

माही की गूंज, मंदसौर।

अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी बी एल बिश्नोई के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नूतन हाई स्कूल मंदसौर में किया गया। कार्यक्रम में महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में उड़ान संस्था की ओर से श्रीमती संगीता कुंभकार ने माहवारी स्वच्छता एवं उसके प्रबंधन के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट आफ मदर एंड चाइल्ड के जिला संयोजक सोनिक मिश्रा द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों के साथ परिचर्चा की गई, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह एवं उसके दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए सहायक संचालक पीसी चौहान द्वारा बाल विवाह न करने एवं ना होने देने हेतु अपील की गई। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मंदसौर उमराव सिंह जैन द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु शपथ दिलाई गई। इस दौरान परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बी आर मुजावले पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पाकिस्तानी चालाकी मे डूबे बांग्लादेशी और बांग्लादेश से भारत रहे सतर्क

माही की गूंज, झाड़ा।

भारत भूमी पर 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मैदान में इस्लामी आतंकवादियों ने पर्यटकों के समूह पर हमला किया, जिसमें नाम धर्म पूछ कर गोली चलाई गई। इस इस्लामी आतंकी हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी और 20 के लगभग घायल हो गए थे। एक ऐसा ही और इस्लामी आतंकी हमला बांग्लादेश के ढाका में 1 जुलाई 2016 में हथियारों से लेस आतंकियों ने किया था। जिसमें भी नाम देश और धर्म पूछकर गो लिया चलाई गई थी। उस इस्लामी आतंकी हमले में तीन बांग्लादेशी, सात जापानी, नो इटालीयन, और एक भारतीय की मौत हो गई थी। गौर करने वाली बात है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में जिन इस्लामी सात आतंकियों को मृत्यु दंड दिया गया था 30 अक्टूबर को वह सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई।

1 जुलाई को ढाका में हुए इस्लामी आतंकी हमला में ढाका के पंश डिव्लोपमेंटिक क्षेत्र में आर्टिशन बेकरी रेस्टोरेंट पर भारी हथियारों से लेस आतंकीयों ने हमला किया था। 20 से अधिक मौतों के साथ दर्जनों को बंधक बनाया गया था। और ऐसे निर्मम हत्याकांड करने वालों के साथ बांग्लादेश ने उदारता दिखाई और बेवजह भूटके, खुंखार आतंकवादियों की सजा में बदलाव कर दिया गया।

बांग्लादेश के जन्म से ही भारत तरह-तरह की दुविधाओं से घिरता रहा और स्वयं को संभालता रहा। 1947 में जब काँग्रेस की सहमती से भारत का विभाजन धर्म का आधार पर किया जा रहा था तब बंगाल को भी विभाजन इसी प्रकार किया गया। हिंदु बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल कहलाया और

मुस्लीम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल कहलाया। अब पूर्वी बंगाल 1955 में पूर्वी पाकिस्तान बना, परंतु इसके पहले पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान की बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। और अर्ततः पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल का नाम बदल कर पूर्वी पाकिस्तान रख दिया गया। यातनाएं बढ़ने लगी और तब शेख मुजीब रहमान की अगुआई में स्वतंत्रा आंदोलन की शुरुआत की गई। रक्त रंजीत संघर्ष हुआ, हजारों मारे गए युद्ध की भारी स्थिती से बचने के लिए नब्बे लाख से ज्यादा लोग भारत की सीमा पर शरणार्थी बनकर चले गए। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जिसके प्रधानमंत्री शेख मुजीब बने जिनकी हत्या हुई थी उसके बाद वहां सैन्य शासन लगा था।

1971 के बाद से ही बांग्लादेश में भी भारतीय और हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद से ही हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हैं जबकि भारत ने करोड़ों बांग्लादेशियों को अपनी शरण में रखा हुआ है, भारत को उन सभी को भारते खदेड़ना होगा। भारत ने जब पाकिस्तान के इस्लामी आतंकी हमले का उत्तर दिया उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने



के समाचार लगातार आते रहे हैं। इससे यब स्पष्ट होता है कि, मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार न तो राजनीतिक स्थिरता बहाल कर पाई है न ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाई है।

मोहम्मद यूनूस अपने बल पर अंतरराष्ट्रीय वित्तिय नेटवर्क में पैठ जमाए हुए थे और उसी का लाभ लेते हुए यूनूस ने जो बाइडन की चुनाव में वित्तीय सहायता भी की थी, किंतु ट्रम्प जीत गए और ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी थी व्यक्त की थी। यूनूस स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे।

और ऐसा हुआ भी। अमेरिका की बात बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमां से हुई फिर यूनूस सरकार ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में बांग्लादेश की भूमि पर अमेरिका को कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी। ताकि चीन और म्यांमार का प्रभाव बंगाल की खाड़ी के कम किया जा सके। बहुत की बातों में तनाव बढ़ता दिखाई दिया तब जनरल वकार ने संकेत दिया कि ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा।

अब उधर दोहरी चाल में यूनूस की नीति का परिणाम है, फिर इस दौरान पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों और अन्य

भारत से तो पहले ही वे तनातनी बढ़ा चुके थे। फिर अपनी सत्ता बरकरार करने के लिए मोहम्मद यूनूस ने चीन का सहारा लिया। चीन की खुश के लिए यूनूस ने यह तक कह दिया कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से काट सकता है। इस क्षेत्र में समुद्र में वह अकेला है उसका इशारा चीकन नेक या सिलिगुड़ी कॉरिडोर को लेकर था। इस कॉरिडोर के उतर में चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनात कर रखी है। यूनूस तो चीन को यह भी संदेश देकर आए कि भारत चीन टकराव की स्थिति में आए तो बांग्लादेश चीन का साथ देगा। यूनूस बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा खेल खेलने को तैयार है वह तो यह भी चाहता है कि अमेरिका उसकी सुध ले

इस्लामिक कट्टरपंथियों की ताकतों को बांग्लादेश में मजबूत होने का पुरा मौका मिल गया। वे महिलाओं को अधिकार देने का खुलकर विरोध कर रहे हैं और जिहादी भारत को धमकाने में लगे हैं। तुर्किए का एनजीओ समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश का समर्थन करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी भारत में बसे बांग्लादेशी लोगों को भारत के विरुद्ध उपयोग करने में पुरी तरह से लगे हुए हैं।

हालांकि भारत देश के अंदर छुपे दुश्मनो को ढुंढ रहा है फिर भी भारत को चीगुनी गति से कार्य कर रोकिया और बांग्लादेशियों को चुन-चुन कर बाहर निकालना चाहिए, गुजरात ने शुरुआत की लेकिन कुछ समय के बाद वहां भी अभियान धीमी गति में पहुंच गया। फिलहाल नेपाल बार्डर पर भी तैनाती बढ़ी दी गई है।

बहरहाल भारत देश के अंदर भारत में ही रहकर भारत में ही पोषित होते हुए भी भारत के विरुद्ध षड़यंत्र रचते है ऐसे देशद्रोहियों का भारत में अब सफाया करने का समय आ गया है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो सबकुछ सहन कर ले। भारत अब प्रश्नों के उत्तर और प्रतिउत्तर भी देना जानता है। भारत के विरोध में जितनी भी विचारधाराएं है उन्हें भारत अपने अनुसार सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, और ऐसी विचारधाराओं को नष्ट करना ही चाहिए जो भारत के मूल, उसकी संस्कृति, और उसके सनातन विचार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।



रिंकेश बेरागी

वीडियो बना रहे शरूख और गार्ड में हुई बहस

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर धाम में दर्शन करने गए एक इंफ्लूएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसमें कपल मंदिर प्रशासन पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर मंदिर प्रशासन तक ने इस मामले में अपना जवाब दिया है।मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर धाम की महिला अपरम पार है। हर साल लाखों से अधिक की संख्या में लोग बाबा का दर्शन करने आते है और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन वहां जाने कई लोग वीआईपी कल्चर को लेकर भी अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस बार एक इंफ्लूएंसर ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली है, जो वायरल हो गई है।

दरअसल, इंफ्लूएंसर नैना अपने पति अर्पित के साथ बाइक से ट्रेवल करते हुए महाकालेश्वर पहुंची होती है और वहां जाकर मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर उनकी सिक्वोरिटी से बहस हो जाती है। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आता है, मंदिर प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी

अ प न ी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके अलावा यूजर्स ने भी वीडियो पर कमेंट्स में जमक कर अपनी राय रखी है। मंदिर में वीडियो बनाना मना

है।उज्जैनमहाकालेश्वर दर्शन करने गई महिला वीडियो में बताती है कि सुबह साढ़े 5 बजे लाइन में लगने के बाद साढ़े 7 बजे मेरा नंबर आता है। फिर मेरे हाथ में फोन देखकर एक महिला सिक्वोरिटी गार्ड भड़क जाती है, तो मैं उसे बताती हूं कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूं। फिर एक पुरुष गार्ड आता है और वह महिला पर चिल्लाना शुरू कर देता है। आगे महिला बताती है कि जब उसकी पति इस बात के लिए विरोध करता है और कहता है



कि आप लोग गलत करेंगे, तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, यह सुनकर सिक्वोरिटी वाले उन दोनों को कंट्रोल रूम ले जाते हैं। जैसे वह कोई अपराधी हो। इसके बाद क्लिप के अंत में महिला पूछती है कि सिक्वोरिटी ने पहले हमारी चेकिंग क्यों नहीं की। वह यह भी मुद्दा उठाती है कि जो सेंट्रलाइज्ड महाकाल में आते ही जिसमें दावा किया गया कि नियम केवल आम भक्तों पर लागू किए जा रहे हैं, वीआईपी को जल्दी निकाल दिया जाता है। इस वीडियो



इस पूरे मामले के वायरल होने पर कट्टर क्रिएटर नैना के पति अर्पित का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अर्पित और मंदिर के कर्मचारियों के बीच बहस देखी जा सकती है। वापस लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि नियम केवल आम भक्तों पर लागू किए जा रहे हैं, वीआईपी को जल्दी निकाल दिया जाता है। इस वीडियो

के वायरल होने के बाद यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में जमक कर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो बनाने को लेकर बहस

उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने इस मामले पर कहा कि 'महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना या उसका इस्तेमाल करना सख्त मना है। साथ ही, किसी महिला की जांच करना अशोभनीय है... फिर भी, कपल रील बना रहा था और प्राइवेट गार्ड द्वारा ऐसा न करने को कहने पर पर हंगामा करने लगा।' मंदिर के प्रथम कौशिक ने कपल के दावों पर बात करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में नैना के पति 'गणेश मंडपम' के अंदर वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने उन्हें केवल नियमों का पालन करने के लिए कहा था, और उस व्यक्ति ने गुस्सा दिखाया।

लोगों की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए जहां कुछ यूजर्स नैना और उसके पति की तरफदारी कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि अगर मंदिर में फोन बैन है, तो नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जबकि उनकी वायरल वीडियो में अनुष्का-विराट की क्लिप देखकर भी कई लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वह उनकी श्रद्धा पर कैसे सवाल उठा सकती है?

नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा

माही की गूंज, अलीराजपुर।

म.प्र शासन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण, सतत प्रवाह एवं समग्र विकास हेतु 'नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा' का आयोजन 25 से 28 मई 2025 तक अलीराजपुर जिले के सोडवा विकासखंड में किया गया।

यात्रा के तीसरे दिन बड़ी सिरखड़ी, उमरठ, साकड़ी, गुलवट एवं टेमला ग्रामों में श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जनसंपर्क, सर्वेक्षण एवं चौपालों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं नर्मदा सेवा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ग्राम वासियों को सामूहिक रूप से जल संरक्षण, स्वच्छता एवं नर्मदा सेवा की शपथ दिलाई गई। साथ ही नर्मदा बेसिन क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आग्रह किया गया, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए नदी क्षेत्र की हरियाली में वृद्धि हो सके।

इस अवसर पर प्रदीप सोलंकी, नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि छगन सिंह सस्तीया, एवं समाजसेवी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा नदी केवल जीवनदायिनी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक भी है।

यात्रा में जिला समन्वयक दीपक जगताप, विकासखंड समन्वयक राम सिंह निगवाल एवं नगरिया सस्तीया, नवांकुर समिति सदस्य ओपसिंह सोलंकी, प्रस्फुटन समिति सदस्य, एवं सीएमसीएलडीपी छात्र भंगड़ सिंह ओहरिया की सक्रिय सहभागिता रही।

यह यात्रा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियानों की एक सशक्त कड़ी है, जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना है। उक्त जानकारी जिला समन्वयक द्वारा दी गई।



गर्भपात के लिए भटकती रही रेप पीड़िता

माही की गूंज, धार।

तिरला क्षेत्र की 13 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसके गर्भपात होने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को उसे परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को पीड़िता के पिता धार पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आगामी प्रक्रिया करने के लिए कहा, लेकिन विभाग द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर तक मामला पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर उसे एंबुलेंस कराई गई।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी भटकते रहे परिजन

मामले में वकील नवनीत जैन ने बताया कि हम लोग पीड़िता की ओर से उसके गर्भपात की प्रक्रिया के लिए निवेदन करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संयोग से केंद्रीय राज्यमंत्री दौरे पर थीं और हमने नाबालिग के पिता के माध्यम से आवेदन दिया, तब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शिंदे ने बताया कि विभाग द्वारा सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं और कोर्ट के आदेश का समय पर पालन किया गया है। बालिका को एंबुलेंस के माध्यम से इंदौर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 24 सप्ताह का गर्भ होने के कारण गर्भपात करने की अनुमति केवल मेडिकल कॉलेज को होती है। अब वहां उसकी जांच आदि के बाद गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वया है पूरा मामला?

दरअसल, धार जिले के एक गांव की 13 साल की नाबालिग को 3 महीने पहले कुछ बदमाश अंगवा कर अहमदाबाद ले गए। लड़की के गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब पीड़िता नाबालिग अपने घर पर लौटी तो उसने परिजनों को पूरा वाक्या बता दिया। उसने बताया कि युवक ने उसके साथ गलत काम किया है, इससे किशोरी प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई, जब नाबालिग के पेट में दर्द बढ़ा। महिला डॉक्टर को दिखाने पर किशोरी के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई।

अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं (जेंडर चैम्पियन) के साथ संवाद कार्यक्रम एवं उदित योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत जिले में बुधवार को ग्राम पंचायत नानपुर में शाला?यागी बालिकाओं के साथ बाल विवाह, माहवारी, स्वच्छता एवं साइबर फ्राडम विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती कस्तुरी किराड, सुरेश वास्कुले ममता यूनिसेफ जिला समन्वयक, सहित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ शाखा प्रभारी कैलाश डुड्डे एवं पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई।



महिला सशक्तिकरण की मिसाल



माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले की एक ऐसी ही महिला की कहानी है जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर दिनभर रिक्शा चलाकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रही है। बड़ा ईटारा निवासी मनीषा बघेल जो की गरीब आदिवासी परिवार से है उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने लिए रिक्शा लाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई सालों से रिक्शा चलाकर अपने पति के साथ परिवार चलाने में हथ बटाती है। वह दिन के 7-8 घंटे रिक्शा चलाती हैं तथा घर खर्च में मदद करती है। मनीषा ने बताया कि वह स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष होने के साथ ही वह गांव संगठन से भी जुड़ी हुई है उन्होंने बताया की उन्होंने पहले आजीविका मिशन के माध्यम से एक लाख रुपये का लोन निकाला था, जिसमें उन्होंने रिक्शा खरीदा और रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण के साथ अपने घर का खर्चा उठाने में पति की सहायता करती है। इसके उपांगत उन्होंने आजीविका मिशन के माध्यम से 40 हजार रुपये का लोन निकाला जिसमें उन्होंने अपनी किराना दुकान व सिलाई की मशीन खरीद कर दुकान संचालन के साथ समय मिलने पर सिलाई का कार्य भी करती हैं, उन्होंने समूह के माध्यम से 20 हजार रुपये निकाले थे जिसे उन्होंने बकरिया खरीदी थी आज उनके पास कई सारी बकरियां है उन्होंने बताया महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकल कर काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। कई परिवार ऐसे होते है जो महिलाओं को बाहर काम करने से रोकते है, किंतु अगर मन कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्पित हो, परिजनों का सहयोग हो तो महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर घर चलाने में आर्थिक सहयोग कर सकती है। मनीषा बघेल नारी शक्ति को यह संदेश दिया कि वह घर के काम के साथ साथ बाहर भी आकर काम करे तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उनका छोटा सा सहयोग परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती देना तथा स्वयं को सशक्त बनाएगा।

पुलिस की आई.बी. अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, उज्जैन।

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और इंटे्लिजेंस ब्यूरो (आई.बी.) के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बीती रात पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई। अधिकारियों ने इसे समन्वय बैठक नाम दिया। बैठक में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षकगण, समस्त थाना प्रभारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में उज्जैन जिले की संवेदनशीलता और भौगोलिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु मंथन

हुआ।एसपी शर्मा के अनुसार बैठक में प्रमुख बिंदु एवं निर्देश इस प्रकार रहे-

गुंडा/बदमाशों पर सतत निगरानी हो। विशेष रूप से शाम एवं रात्रिकालीन समय में थाना क्षेत्र में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सामाहिक अथवा रैडम चेकिंग अनिवार्य रूप से की जाए। होटल, लॉज, ढाबा आदि की नियमित जांच हो। सदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए लगातार निरीक्षण किया जाए।

सिम कांड विक्रेताओं की जांच हो।सिम बेचने वाले दुकानदारों को थानों में बुलाकर दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाए। उनके

व्यवसायिक क्रियाकलापों की निगरानी की जाए।

सदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो सिमी, पी.एफ.आई. अथवा अन्य सदिग्ध संगठनों से संभावित रूप से जुड़े हों या बाहरी/बंगाली मूल के रहवासी अथवा व्यवसायी हों, उनकी गहन जांच की जाए। ई-रक्षक एप के माध्यम से आधार या अन्य वैध पहचान-पत्रों से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। फर्जी दस्तावेज की स्थिति में कार्यवाही हो। दस्तावेजों में भिन्न फोटो या जानकारी पाए जाने पर गंभीरता से जांच की जाए। सदेहास्पद मामलों में संबंधित व्यक्ति का सी.डी.आर. तलब कर सत्यापन

शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा 4 और 5 जून को, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

माही की गूंज, उज्जैन।

गंगा दशमी पर्व पर 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शामिल होना प्रस्तावित है। निगम अध्यक्ष कलावती यादव और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने परिक्रमा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में नरेश शर्मा, अनोखीलाल शर्मा, निगमायुक्त आशीष पाठक भी उपस्थित थे। सभी ने पूजा स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था,घाटों की साफ सफाई, विभिन्न स्थानों पर रंग-रोगन करवाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का संकल्प रामघाट से लिया जाएगा।

क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति की बैठक संपन्न

शिप्रा तीर्थ परिक्रमा अंतर्गत विक्रमादित्य शोधपीठ कार्यालय में क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति की बैठक हुई। शिप्रा लोक संस्कृति समिति के सचिव नरेश शर्मा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, भाजपा नगर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल भाजपा एवं समाज सेवी रवि सोलंकी उपस्थित थे। बैठक में यात्रा मार्ग में आने वाले पड़ाव स्थलों के संबंध में चर्चा की गई। 4 जून को सायं 7 बजे दत्त अखाड़ा घाट पर पवन तिवारी की भजन प्रस्तुति होगी। 5 जून को शिप्रा परिक्रमा



के समापन पर रामघाट पर चुनरी अर्पण कार्यक्रम, आर्मी सिंफनी बैंड की प्रस्तुति होगी। पश्चात गायिका स्वस्ती मेहुल प्रस्तुति देंगी। 5 से 16 जून तक प्रतिदिन सायं 7 बजे से पं. ढोली बुआ, ग्यालियर द्वारा हरिकथा एवं नारीय कीर्तन की प्रस्तुति रामघाट पर दी जाएगी।

सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत घाट निर्माण कार्य का होगा भूमिपूजन

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा शनिवार 31 मई को वरुंअली आगामी सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले घाट निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा साथ ही 83.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैराज/स्टॉप डेम/वेटेडकाँजवे का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका निगम के द्वारा 1.39 करोड़ रुपए की लागत से कालियादेह स्टॉप डेम के मरम्मत कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्व 2028 पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई के द्वारा क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक कुल 29.21 किलोमीटर लम्बाई में कुल 778.91 करोड़ रुपए की लागत से घाट निर्माण कार्य किया

जाएगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

जल संसाधन विभाग के द्वारा जानकारी दी गई की क्षिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान हेतु आवश्यक जल स्तर व आवागमन बनाए रखने हेतु वेटेड काँजवे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए क्षिप्रा नदी को अवरिल एवं प्रवाहमान बनाने हेतु क्षिप्रा नदी पर उज्जैन जिले, इंदौर जिले एवं देवास जिले बैराज का निर्माण एवं स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य भी किया जावेगा। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा 30 माह रखी गई है।गौरतलब है की उज्जैन शहर पवित्र मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है। उज्जैन शहर का पौराणिक व धार्मिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर सिंहस्थ (कुंभ) पर्व पर मेले का आयोजन होता है। क्षिप्रा नदी को अवरिल एवं प्रवाहमान बनाने एवं श्रद्धालुओं एवं साधु संतो के स्नान

हेतु घाटों का निर्माण किया जाएगा।

वैराज / स्टॉप डेम/ वेटेड काँजवे

जल संसाधन विभाग के द्वारा जानकारी दी गई की क्षिप्रा नदी पर जल संसाधन विभाग देवास के द्वारा 2.53 करोड़ रुपए की लागत से गाजनोद खेड़ा बैराज ,3.23 करोड़ रुपए की लागत से दखनाखेड़ी बैराज , 3.15 करोड़ रुपए की लागत से पेटाड़ी बैराज कम काँजवे , 3.79 करोड़ रुपए की लागत से रनायर बैराज ,4.73 करोड़ रुपए की लागत से टिगरियागंगा बैराज , 6.74 करोड़ रुपए की लागत से सिरांज बैराज कम काँजवे और 2.57 करोड़ रुपए की लागत से बरोदपिलिया बैराज का निर्माण किया जाएगा।

नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई उज्जैन के द्वारा क्षिप्रा नदी पर 8.71 करोड़ रुपए की लागत से किट्टोदाराव स्टॉप डेम तथा कान्ह



नदी पर 5.74 करोड़ रुपए की लागत से पंथपिललाई स्टॉप डेम, 4.56 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुरा स्टॉप डेम,6.24 करोड़ रुपए की लागत से गोठड़ा स्टॉप डेम, 5.06 करोड़ रुपए की लागत से पिपलियाराघी क्रमांक 02 बैराज और 6.34 करोड़ रुपए की लागत से रामवासा क्रमांक 02 बैराज का निर्माण किया जाएगा । जल संसाधन विभाग इंदौर के द्वारा 2.69 करोड़ रुपए की लागत से

ब्राह्मणपिलिया स्टॉप डेम , 2.64 करोड़ रुपए की लागत से दर्जीकराडिया स्टॉप डेम, 1.96 करोड़ रुपए की लागत से कुडाना स्टॉप डेम , 3.43 करोड़ रुपए की लागत से कायस्थखेड़ी स्टॉप डेम , 4.32 करोड़ रुपए की लागत से साहदा स्टॉप डेम ,0.53 करोड़ रुपए की लागत से लालखेड़ी स्टॉप डेम मरम्मत कार्य और 4.43 करोड़ रुपए की लागत से मेलकलमा बैराज सहपुलिया का

निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका निगम उज्जैन के द्वारा 1.39 करोड़ रुपए की लागत से कालियादेह स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य किया जाएगा।कान्ह नदी पर उज्जैन जिले में 05 बैराज एवं इंदौर जिले में 06 बैराज, इस प्रकार कुल 11 बैराजों का निर्माण किया जावेगा। इस प्रकार क्षिप्रा एवं कान्ह नदी पर कुल 21 बैराजों/स्टॉप डेम का निर्माण किया जावेगा।

